शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

# राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 3 ■ अंक 02 ■ मई 2019 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 32

# भारत की वैश्विक जीत

# परिषद् गतिविधियां

संविधान के शिल्पी बाबा साहेब भीमराव रामजी आंबेडकर को अभाविप ने किया याद

गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) नक्सली हमला में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते अभाविप कार्यकर्ता

राष्ट्रीय
# छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 3, अंक 02
मई, 2019

**संपादक**
आशुतोष भटनागर
**संपादक–मण्डल :**
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

**संपादकीय पत्राचार :**
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

# इस अंक में

## 05 आतंक पर भारत की वैश्विक जीत

आतंक की खेती करने वाला, पुलवामा हमला का गुनहगार मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है। पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश - ए - मोहम्मद...

| | |
|---|---|
| संपादकीय | 04 |
| DOES PAKISTAN REALIZE ITS COMPULSIONS ? | 09 |
| अभाविप ने किया बाबा साहेब को याद, 128वीं जयंती पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित | 12 |
| देश की नदी घाटियों में नहीं है सूखे से उबरने की क्षमता | 13 |
| चक्रवाती तूफान फेनी से प्रभावित राज्यों में नीट की परीक्षा के आयोजन हेतु विकल्पों पर शीघ्र विचार हो : अभाविप | 14 |
| एसिड हमले के खिलाफ़ एकजुट हो भारत | 15 |
| युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार : भुपेन्द्र नाग | 16 |
| सभ्यतागत समझ और विभाजन की गुत्थी | 17 |
| साहसी फिल्म 'द ताशकंद फाइल्स' जिसे दस साल पहले बनाना नामुमकिन था | 19 |
| गंभीर खतरे की आहट है श्रीलंका आतंकी हमला | 21 |
| श्रीलंका में निरंतर हुए आत्मघाती हमलों में सैकड़ों नागरिकों की मृत्यु बेहद दुर्भाग्यपूर्ण: अभाविप | 23 |
| 'वसुधैव – कुटम्बकम्' को चरितार्थ करता विश्व विद्यार्थी युवा संगठन (WOSY) | 24 |
| THINK INDIA ORGANISED CHANDIGARH DIALOGUE | 26 |
| अभाविप ने किया तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) के खिलाफ प्रदर्शन | 27 |
| परिचर्चा : श्रीलंका की घटना क्या भारत के लिए चेतावनी है ? | 29 |

**वैधानिक सूचना :** राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

# संपादकीय

देश में चुनाव का वातावरण है। विभिन्न राजनैतिक दल अपनी-अपनी जीत के लिये सारे उपाय आजमा रहे हैं। दौड़ में खुद को आगे निकालने से ज्यादा कोशिश इस बात की है कि प्रतिपक्षी कैसे पीछे रहे। इसके लिये सही-गलत और सच-झूठ की परवाह किये बिना एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर जारी है।

तीन दशक पहले तक भारत चुनाव को उत्सव की तरह मनाता था। रंग-बिरंगी पोशाकों में कौतुक दिखाते प्रत्याशी के समर्थक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते थे। नाचते-गाते-झूमते महिला-पुरुष मतदान के लिये जाते थे। इस उत्सवधर्मिता के बीच कोई राजनेता यदि अपने प्रतिद्वंदी पर अभद्र टिप्पणी कर दे तो प्रतिपक्ष ही नहीं, उसके अपने दल के लोग भी उसे मर्यादा में रहने की नसीहत देते थे। इक्कीसवीं सदी ने इसे भी बदल दिया है।

तीन दशक पहले का चुनावी नारा होता था – हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। इस नारे की चरम परिणति तो मनरेगा के जॉब कार्ड में हुई, साथ ही बदलती प्रौद्योगिकी ने हर हाथ में फोन और कैमरा भी थमा दिया। हर कोई अपने राजनैतिक आका के सच-झूठ को आगे बढ़ाने में लगा है। तथ्यों को जांचने परखने का समय किसी के पास नहीं है। जैसा आया, वैसा आगे बढ़ा दिया। एक आभासी दुनिया में सब एक दूसरे को सपने बेचते-बेचते कब झूठ के व्यापार का हिस्सा बन गये, पता ही नहीं चला।

चुनाव पर भ्रष्टाचार का साया पड़ा तो अनजाने कोनों से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करने की हठ लिये आंदोलनकारी प्रकट हो गये। जिन्होंने आंदोलन किया, जेल गये, कष्ट सहे और इसकी कीमत नहीं मांगी, वे विचार आधारित संगठन कदम-कदम आगे बढ़े। जिन्हें इसकी आड़ में जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेने की जल्दी थी, वे उसी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबने-उतराने लगे। यह 1977 में भी हुआ और 2014 में भी। इसके पीछे कोई विचार नहीं बल्कि विरोध ही इनका विचार था। इस अविचारित विरोध की परिणति अराजकता में हुई।

1977 और 2019 में कुछ बुनियादी फर्क हैं। तब राजनैतिक विचारधाराओं के संघर्ष के बीच राष्ट्रीय विचार हाशिये पर था। आज राष्ट्रीय विचार विमर्श के केन्द्र में है और विरोध में ऐसे दल हैं जो अपनी संकुचित विचारधाराओं और जाति और सम्प्रदाय की राजनीति के खोल से बाहर आने को तैयार नहीं। चुनाव को उत्सव से हटा कर कर्तव्य के नीरस चौखटे में तय करने वालों ने इसे राजनीति में शुचिता स्थापित करने का तर्क दिया था। आज वह शुचिता तार-तार है। सभी राजनैतिक दलों में शब्दों मर्यादा को न मानने वाले लोग मौजूद हैं और अधिकांश दलों का नेतृत्व अपने आपको नैतिकता के बोझ से मुक्त कर चुका है। झूठे आरोप लगाने में उनकी जबान नहीं लड़खड़ाती। फर्जी आंकड़े देते उनकी आत्मा उन्हें नहीं धिक्कारती। परिणामस्वरूप, इस चुनाव में राजनीति की गरिमा को हम निम्नतम स्तर पर जाते हुए देख रहे हैं।

एकमात्र स्थायी तत्व परिवर्तन है। इसलिये यह अवसर है कि देश का युवा इस राजनैतिक निम्नता को नकार कर मूल्याधारित उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना का एक नया अध्याय लिखे। किसी भी लोकतंत्र में इसका रास्ता मतदान से होकर जाता है। इसलिये अधिकतम मतदान और विचारपूर्ण मतदान के लिये अधिकतम प्रयत्न आज की आवश्यकता हो। आज ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व को सत्ता सौंपे जाने की जरूरत है जिसके सामने भविष्य के भारत का सपना हो और दल और सत्ता की राजनीति से ऊपर उठ कर देश के पक्ष में निर्णायक फैसले लेने का साहस हो। परिषद कार्यकर्ता इस सामयिक चुनौती के लिये सक्रिय होंगे और अनुकूल परिणाम आने तक बने रहेंगे।

शुभकामना सहित,

आपका

संपादक

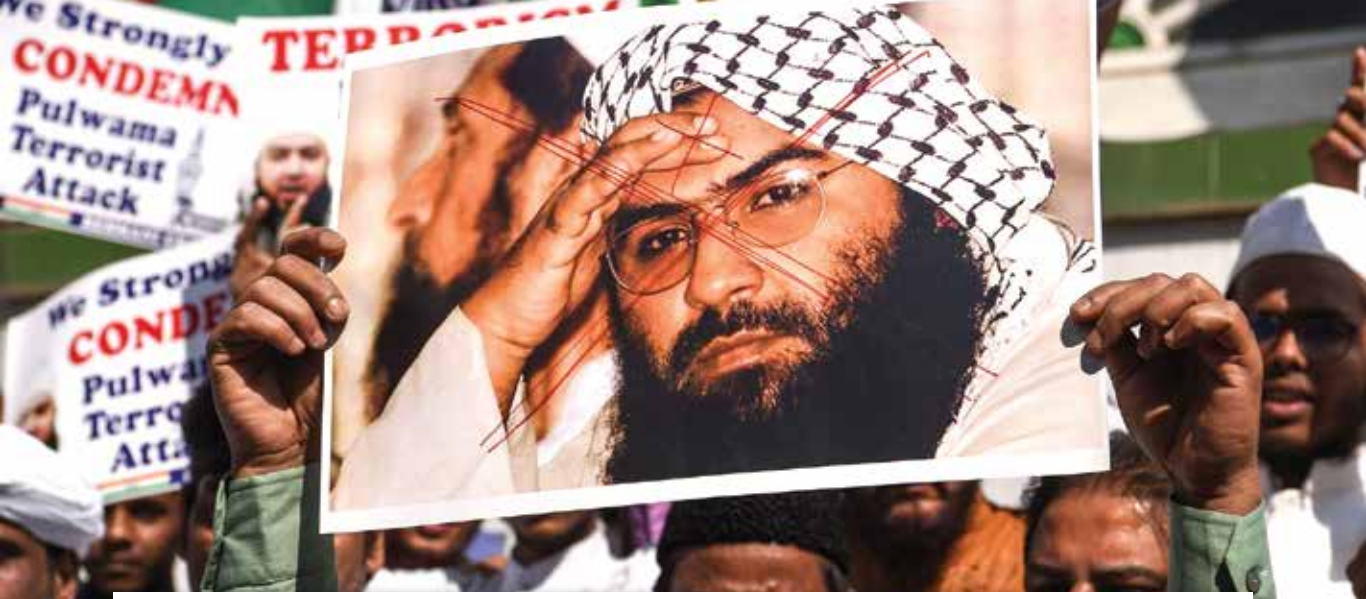


# आतंक पर भारत की वैश्विक जीत

**| अजीत कुमार सिंह |**

आतंक की खेती करने वाला, पुलवामा हमला का गुनहगार मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है। पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश - ए - मोहम्मद के सरगना मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की पिछले दस वर्षों में यह चौथी कोशिश थी । दरअसल, चीन संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद् का अकेला ऐसा देश है जो मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध करता रहा है लेकिन इस बार भारत की बेहतरीन कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन को झुकना पड़ा और 01 मई 2019 को मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में दुनियाभर के देशों का साथ दिया । दुनिया भर के सभी देशों ने जिस तरह से भारत का साथ दिया इससे साफ होता है कि विगत कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर भारत की धाक बढ़ी है । पूरा विश्व यह जान चुका है कि भारत अब सहने के मूड में नहीं है । अगर पाकिस्तान के वजीर अब भी भारत में आतंकी हमला करने वाले संगठनों को पनाह देना जारी रखेंगे तो उनके खिलाफ जल्द ही एफएटीएफ (फाइनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्स) का फंदा भी तैयार हो सकता है । संभव है कि भारत एफएटीएफ में पाकिस्तान को घेरने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले को भी उठायेगा । भारत की लगातार कोशिशों को आतंकवाद के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए । भारत ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उन्हें सबक दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली उसकी नीति अब नहीं चलेगी । जब भी पाकिस्तानपरस्त आतंकवादी भारत में हमला करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा । भारत की कूटनीतिक कोशिशों से पाक को समझ जाना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा मित्र देश भी उसके आतंकी चेहरे पर पर्दा नहीं डाल सकता ।

## यूं भारत की कूटनीति में फंसा चीन

अजहर को 1994 में कश्मीर में जाली पहचान और दस्तावेजों के आरोप में गिरफ्तार किया था लेकिन 31 दिसंबर 1999 को कंधार विमान अपहरण के दौरान

# जानें कौन है मसूद अजहर
## जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाया प्रतिबंध

खूंखार आतंकी मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया है जो पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। मसूद अजहर ने मार्च 2000 में हरकत-उल-मुजाहिदीन में विभाजन करवाकर यह संगठन बनाया था। मसूद अजहर को साल 1994 में श्रीनगर पर हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन, 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड के बाद भारत सरकार को उसे रिहा करना पड़ा था। इसके अगले ही साल उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम से आतंकवादी संगठन बना लिया। लेकिन, साल 2002 में पाकिस्तान सरकार ने जैश पर बैन लगा दिया। मसूद अजहर भारत में अब तक कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। 13 दिसंबर 2001 को मसूद अजहर ने ही भारतीय संसद पर हमला कराया था। इससे पहले अक्टूबर 2001 में ही उसने जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर भी आतंकी हमला कराया था। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट में वायुसेना की छावनी पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही था। इसके अलावा, इसी साल 14 फरवरी को पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली थी।

पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश लाहौर के पास रची गई थी। आतंकियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान के चकलाला और लायलपुर एयरबेस पर दी गई थी। हमले के वक्त आतंकियों के चारों हैंडलर्स पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट और शकरगढ़ में मौजूद थे। जैश का सरगना मसूद अजहर, उसका भाई रउफ असगर, उनके दो साथी अशफाक और कासिम हमलावरों को आदेश दे रहे थे। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का आरोप भी मसूद अजहर पर लगा था।

इसी साल 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की जैश-ए मुहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ, जब सीआरपीएफ के ज्यादातर जवान अपनी छुट्टिया खत्म कर वापस श्रीनगर ड्यूटी पर लौट रहे थे। आदिल अहमद डार नाम के आत्मघाती हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसने विस्फोटक से भरी कार ले जाकर सीआरपीएफ के काफिले से भिड़ा दी थी।

बंधकों की रिहाई के बदले में मसूद को मजबूरन रिहा करना पड़ा था। जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कई बड़े आतंकी हमले करवाए हैं, जिसमें संसद पर हमला, मुंबई पर हमला, उरी में सेना के कैंप पर हमला, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, मजार-ए-शरीफ में स्थित भारतीय दूतावास पर हमला, पठानकोट हमला शामिल है। भारत लगातार इस संगठन और इसके आका मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कोशिश करता रहा । पहले 2009, फिर अक्टूबर 2016, फरवरी 2017 और फिर मार्च 2019 में इस बाबत कोशिश की गई थी, लेकिन चीन के वीटो की वजह से यह संभव नहीं हो सका था।

इस वर्ष भी मार्च में मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रस्ताव संख्या 1267 को चीन ने तकनीकी खामियां बताकर वीटो के जरिए रोक दिया था। इसके

बाद अमेरिका ने चीन को इस संबंध में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अमेरिका की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि वह इस संबंध में छह माह का इंतजार नहीं करेगा। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका का कहना था कि मसूद पर प्रतिबंध लगाने का यह सबसे सही समय है, लिहाजा यह मौका किसी भी सूरत में हाथों से नहीं निकलना चाहिए। अमेरिका ने बेहद स्पष्ट शब्दों में चीन को अपनी मंशा जता दी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा भी इस संबंध में लगातार चीन से संपर्क कर वहां के अधिकारियों से वार्ता की जा रही थी। इस संदर्भ में भारतीय विदेश सचिव ने अमेरिका, चीन और रूस की यात्रा की। यह भारत की कूटनीतिक चाल ही थी जिसके बाद चीन को इस बात का डर सताने लगा था कि यदि इस बार उसने पाकिस्ताकन का साथ दिया तो निश्चित रूप से वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग-थलग पड़ जाएगा। तीन देशों के प्रस्ताव को अफ्रीकी देशों समेत यूरोपीय संघ, जापान, रूस और कनाडा का भी समर्थन हासिल था। इसके बाद भी चीन के कदम से पूरी दुनिया हैरान थी। चीन इस बात को भी समझ चुका था कि लगातार इस तरह के अडियल रवैये से वैश्विक मंच पर उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, जिसको वह इस बार खत्म करना चाहता था। परिणामस्वरूप चीन ने एक मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए भारत का साथ दिया । विदित हो कि सिर्फ एक मसूद के मसले पर ही चीन ने भारत की राह में रोड़ा नहीं अटकाया है, बल्कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने के मुद्दे पर भी चीन ने भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया था ।

## सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों का मिला समर्थन

भारत की यह कूटनीतिक जीत सिर्फ चीन के मिजाज में बदलाव लाने के हिसाब से ही अहम नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों का सहयोग हासिल किया है। यह सरकार की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है। वर्ष 2009 में पहली बार भारत ने अजहर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद चार बार ऐसा प्रस्ताव पेश हो चुका है और हर बार चीन उस पर वीटो लगाकर खारिज करवाता रहा है।

## मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने के बाद पड़ेगा ये प्रभाव

- संयुक्त राष्ट्र फैसले के बाद अब आतंकी मसूद अजहर पर शिकंजा कसना शुरु हो जाएगा।
- हथियार खरिदने पर प्रतिबंध
- दूसरे देश की यात्रा करने पर रोक
- मसूद अजहर पर लगेंगी वित्तीय पाबंदियां
- अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित होने वाले शख्स पर कई वित्तीय पाबंदियां लगाई जाती हैं।
- हर संपत्ति को किया जाएगा सीज

## विश्व बिरादरी ने किया फैसले का स्वागत

अमेरिका समेत दुनियाभर के देशों ने मसूद पर पाबंदी लगाने का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि जैश के आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में अमेरिका के मिशन को बधाई देता हूं। यह लंबे समय से प्रतीक्षित कार्रवाई अमेरिकी कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जीत है। दक्षिण एशिया में शांति के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में पेश संशोधित प्रस्तावों का नए सिरे से अध्ययन करने के बाद तकनीकी रोक हटाई गई है। चीन ने यह भी कहा है कि उसे प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं दिखी। चीन ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि वह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर सभी देशों के साथ सहयोग करने को तैयार रहता है। चीन ने अपने बयान में पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ लगातार काम कर रहा है और उसके योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रस्ताव लाने वाले देश फ्रांस ने भी इसका स्वागत किया है।

### पुलवामा हमले के बाद से शुरू हो गई थी प्रकिया

जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को अंतर राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले ने 'ताबूत में कील का काम' किया। बताया जाता है कि पुलवामा हमले के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद को सूचीबद्ध करने की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बारे में सुरक्षा परिषद् ने कड़ा बयान जारी किया था कि इस मामले में पुलवामा लिंक बहुत साफ है। पुलवामा हमले की स्थिति मसूद अजहर के खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने वाली रही। भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंड्रे जिग्लर ने कहा कि हमने साल 2011, 2016 और 2017 में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताह का समर्थन किया था। पुलवामा हमले के बाद हमने पहल की। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने बयान जारी किया था कि हमले के गुनहगार को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देश सर्वसम्मति पर पहुंचे हैं।

### भारत की वो कूटनीतिक कोशिशें, जिससे मसूद अजहर घोषित हुआ अंतर्राष्ट्रीय आतंकी

- पुलवामा हमले के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस से की बात।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों से किया गया संपर्क।
- हर देश को भारतीय विदेश मंत्रालय ने जैश व अजहर की आतंकी करतूतों के दिए सबूत।
- विदेश सचिव विजय गोखले की हाल की चीन यात्रा में जैश की भूमिका को लेकर फिर सौंपे गये सबूत।
- अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, उसके बगैर भी किसी दूसरे तरीके से प्रतिबंध लागू करने की तैयारी।
- संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित 22 आतंकी संगठन पाकिस्तान में है जबकि जितने लोगों को यूएन की विशेष समिति ने आतंकी घोषित किया है उनमें से आधे पाकिस्तानी हैं।
- दुनिया कर्ज में डूबे पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। अब पाकिस्तान को दिखाना होगा कि वह इन आतंकियों के खिलाफ निर्णायक व ठोस कदम उठाएगा।
- भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुस कर वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें यह सबक दिया कि आतंकवाद को बेहद कम लागत पर बढ़ावा देने की उनकी नीति अब नहीं चलेगी।
- भारत की कूटनीतिक कोशिशों से पाकिस्तान को यह बताया गया है कि उनका सबसे बड़ा मित्र देश चीन भी उनके आतंकी चेहरे पर पर्दा नहीं डाल सकता।
- पाकिस्तान के ऊपर अब सबसे बड़ा खतरा एफएटीएफ की काली सूची में जाने का है जिसपर पर अगले महीने फैसला हो सकता है। एफएटीएफ उन देशों को काली सूची में डालता है जो आतंकियों को फंड आदि मुहैया कराने के लिए सख्त कदम नहीं उठाते। ■

*(लेखक 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' पत्रिका के सहायक संपादक हैं।)*

# DOES PAKISTAN REALIZE ITS COMPULSIONS ?

**Dr. K.N. Pandita**

With financial crunch tightening its stranglehold with each passing day, Islamabad is re-evaluating some fundamentals of its domestic and foreign policy with which country's economic stability is closely liked. The apprehensions of Pakistan being listed in FATF, because of not too satisfactory a performance in cutting financial channels of various terrorist organizations, could prove of serious disaster.

A few moves noticed on the regional chessboard of politics are indicative of the necessity under which Pakistan will have to manage its affairs in near future. Foremost is the long drawn fighting in Afghanistan and Pakistan's dubious role. Washington seems to have lowered its tone about curtailment of the activities of Haqqani group in Afghan fighting. It means that Pakistan has discouraged if not fully dismantled safe haven for the Afghan warriors on her, soil particularly in Quetta.

Resumption of talks among the stakeholders in Afghanistan with Pakistan playing a notable role is matched by the faint indication shown by the IMF czars in agreeing to send its fresh delegation to Islamabad for carrying forward the dialogue for about 9 billion-dollar loan package with new perspective and maybe some new conditions.

The issue of listing Jaish-e-Muhammad chief Azhar Mas'ud by the Security Council had taken a new and alarming turn for China which stalled the passing of a resolution three times so far. Three big powers of the SC, the US, UK and France have brought a resolution for general debate and the resultant majority vote which obviously would have gone against China. Caught on the wrong foot, China had of late given an indication that it would advise Pakistan to let Azhar be listed by the SC. (As I am writing these lines the news flash has come that the SC has unanimously listed Azhar as international terrorist)

In a statement given to the press recently, Chinese foreign ministry spokesman had said, "We support the listing issue being

settled within the 1267 committee through dialogue and consultation and I believe this is the consensus of most members. Second, the relevant consultations are going on within the committee and have achieved some progress."

This is the Chinese way of retracting from its known stand. A change of tactics on the part of three permanent members of the SC seems to have had its desired impact. As Chinese spokesman Geng noted that the matter needed to be settled within 1267 Committee, Beijing has remained averse to dealing with the issue in the UNSC where proceedings are public as compared to the sanctions committee, which operates under secrecy.

Senior Pakistani officials disclosed to Dawn that China could lift its technical hold leading to Azhar's designation, while developments in this regard are likely to be shared by the Foreign Office with the media at a special briefing.

This background development trivializes a statement of Pakistani foreign minister Shah Mahmud Qureshi given simultaneously that if India could provide substantial evidence of the involvement of JeM in Pulwama attack, it would strengthen Pakistan's hands in filing a prosecution case in a court of law. India has done the right thing of presenting the plethora of evidence to the SC and not to Pakistan whose behavior is already known in such matters.

In yet another simultaneous development, Alice Wells, Principal Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs, on a two-day visit to Pakistan, met Chairman of the Joint Chiefs of Staff Committee Gen Zubair Hayat, Army Chief Gen Qamar Bajwa, Adviser to Prime Minister on Finance Abdul Hafeez Shaikh, Foreign Secretary Sohail Mahmood, and several other key officials. Her visit coincided with the trip of US Special Envoy for Afghan Peace and Reconciliation Zalmay Khalilzad and the two together held a few meetings.

While Afghan peace talks formed the key of Ambassador Wells' visit, the issue of Pakistan's financial crunch and borrowings from IMF and other lending agencies besides the Azhar Mas'ud case and importantly Indo-Pak situation also came under discussion at these meetings. Her comment to the journalists at the US Embassy in Islamabad was, "We would encourage the parties to move forward with the designation (of Azhar). It reaffirms the centrality of UN and UN role in designating terrorists. We believe designation process should be technical in nature, even assessment of evidence and countries moving forward to ensure that." It has to be noted that last time (third time) when China vetoed the resolution against Azhar, her representative had touched upon the "technical" aspect and the commentators and experts lost no time in remarking that such matters did not entail any technicality. It seems that the US has given China a face-savor.

Pakistan newspaper Dawn has carried parts of the statements of Ambassador Wells given in the course of her interaction with Pakistani officials. These statements give an insight into the lines along which the interaction between the American and Pakistani officials has taken place recently. Of course, we are aware that after a spell of heightened spat, the more pragmatists among the senior echelons in both the countries had counseled for a balanced approach to relationship considering peace and normalcy as the primary requirement for enduring settlement of regional issues. The US embassy in a statement said Amb Wells in her interactions in Islamabad underscored the importance of all actors in the region taking steps to advance security, stability, and cooperation in South Asia.

The Assistant Secretary, who holds the charge of South and Central Asia, was categorical in laying the onus on Pakistan for stabilizing peace in the region by "detailing the steps it had taken to prevent the terrorist groups from fund raising and organizing." This is the crux of the logjam in Indo-Pak talks and the US has, thus, recognized that dismantling the terrorist camps and snapping their funding sources are justifiable conditions for a constructive and meaningful dialogue between India and Pakistan. The

reverberation of this line of thinking is also discernible in the press statement of Pakistani foreign minister to which we have alluded in the beginning of this write up.

Interestingly, the US has shifted the issuance of a verdict on whether or not Pakistan has done enough to contain terror syndrome in that country to the observations of the FATF which are expected to come soon and which will decide where Pakistan stands. FATF report will show to what extent Pakistan has implemented measures that have resulted in cutting of the trail of financial support to the terrorist organizations.

When Ambassador Wells was asked about the status of relationship between India and Pakistan and the possibility of the two countries making a resolve of overcoming their differences, she was emphatic in stating that "it depended on the steps taken by Pakistan government to demonstrate its seriousness in implementing the (National Action) plan."

Again for the first time, Washington conceded in no ambiguous terms that "use of force was the prerogative of the state and those militant groups could not use Pakistani soil. The action against terrorist groups needed to be sustained." This very significant sentence is the candid recognition that India was within its rights to strike at the terrorist camp somewhere in the forests of the Khyber Pukhtunkhwa adjoining the territory of Jammu and Kashmir State which legally belongs to India.

Reverberations of this re-alignment scenario shaping in close proximity of Kashmir are already in the air. As a result of the state unleashing a minimum of its might in literal sense of the term, the militants in Kashmir valley are on the run. This takes away the air from the sails of the separatists and ambivalent politicians who are frantically fraternizing with the secessionists while campaigning for parliamentary election. In their election campaigns they have been turning ire on Prime Minister Modi knowing it very well that people in the valley have lost faith not only in the regional political leadership but are also doubtful whether propagandist material like Article 370 and 35-A have brought them more harm than good. A Kashmiri has to rethink whether his lot with one carrying the begging bowl slung to his neck is desirable and in the interests of this progeny. Pakistan's Ziau'l Haq had said that Pakistan would bleed India in Kashmir. The truth is that it is Kashmir that has bled Pakistan to its last drop and thrown a beggar's scrip round her neck. ■

*(Author is Former Director of Central Asian Studies, Kashmir University)*

## मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'ग्लोबल टेररिस्ट' घोषित किये जाने पर अभाविप ने जतायी खुशी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित होने पर देश के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन करती है तथा समूचे देश को शुभकामनाएं प्रेषित करती है। अभाविप यह आशा करती है कि, जिस प्रकार से भारत की शांति के लिए जैश-ए-मोहम्मद लगातार एक खतरा रहा है, उससे देश को छुटकारा मिलेगा तथा इस आतंकवादी संगठन के सफाई के लिए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत सरकार लगातार जिस तरह से अपने कूटनीतिक प्रयासों से इस निर्णय के लिए प्रयासरत रही है, वह इस सरकार की आतंकवाद के सफाए को लेकर प्रतिबद्धता को स्पष्टता से प्रकट करता है। सरकार के प्रयासों की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हार्दिक प्रशंसा करती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि, मसूद अजहर भारत के लिए एक खतरा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने का निर्णय निश्चित ही बेहद महत्वपूर्ण है। हम यह आशा करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व एकजुट होगा तथा इस अमानवीय एवं घृणित प्रवृत्ति का विश्व की भूमि से हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा।

# अभाविप ने किया बाबा साहेब को याद, 128वीं जयंती पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित

भारत रत्न बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर की 128वीं जयंती पर 14 अप्रैल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देशभर में बाबा साहेब को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया। बाबा साहेब की जयंती पर देशभर में विचार संगोष्ठी, मेडिकल शिविर,संविधान साईकिल यात्रा, बाबा साहेब की रंगोली, माल्यार्पण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुम्बई के कासारवाडी में बौद्धजन पंचायत समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिता दिया। वे जीवन भर गरीबों, दलितों, शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। बाबा साहेब का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो हमें कहीं और देखने को ना मिले। जीवन भर वे दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों व समाज में समानता के लिए आवाज उठाते रहे। श्री चौहान ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा मजदूर वर्ग व महिला के अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत के सविधान निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे कानून, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों के ज्ञाता थे। श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को बाबा साहेब के जीवन को अवश्य पढाना चाहिए ताकि वे उनके संघर्षमयी जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ सकें। दिल्ली में आयोजित संविधान साईकिल यात्रा में शामिल विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। वे जीवन भर समाज सुधारों के लिए संघर्ष करते रहे ताकि समाज में सभी को आगे बढने के समान अवसर मिल सके। बाबा साहेब विश्व के प्रमुख समाज सुधारकों में गिने जाते है। उन्होंने कहा कि परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सामाजिक समरसता के संदेश को देशभर में फैला रहा है। बाबा साहेब का जीवन हमें सदैव समरस भारत बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की रंगोली पर बाबा साहेब का चित्र उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ता ने लोगों को सामाजिक समरसता व भाईचारे का संदेश भी दिया। हरियाणा में बाबा साहेब की जयंती पर मेडिविजन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पीजीआईएम के कार्यकर्ताओं ने 400 से अधिक लोगों की जांच कर उन्हें दवाईयों का वितरण किया और बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ-साथ देशभर के विभिन्न प्रांतों में बाबा साहेब के जीवन पर विचार संगोष्ठियां आयोजित कर बाबा साहेब के सपनों के भारत का संदेश आमजन तक पहुंचाया गया। ■

*(राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए संदीप आजाद की रिपोर्ट)*

# देश की नदी घाटियों में नहीं है सूखे से उबरने की क्षमता

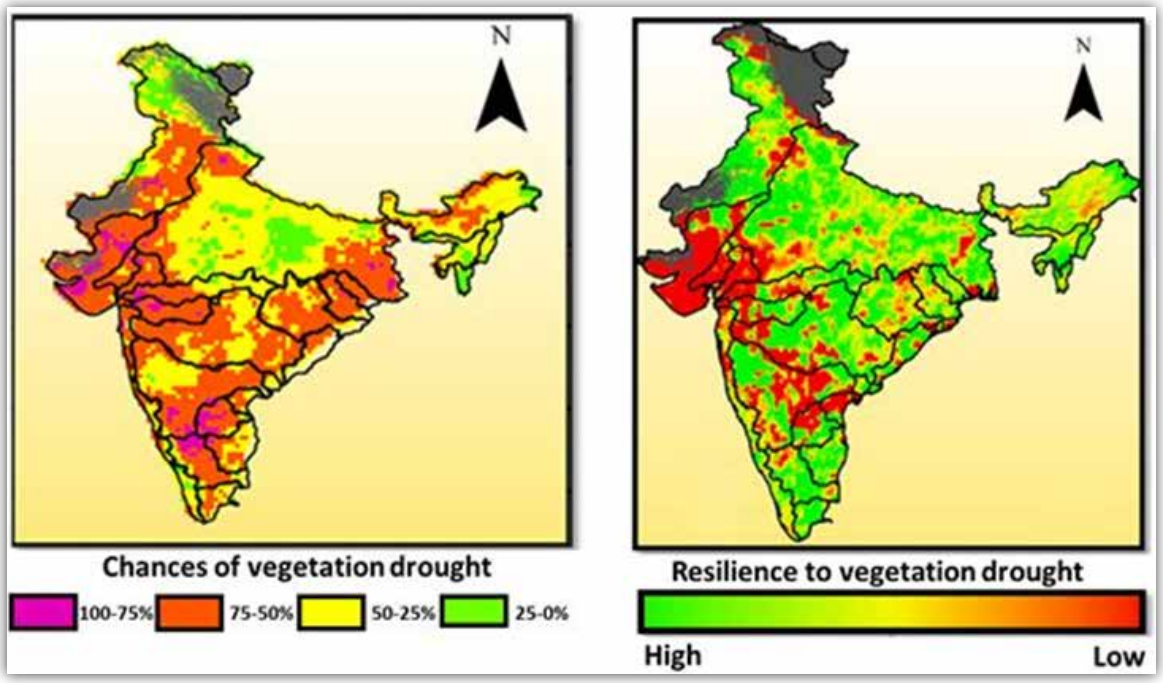


**| उमाशंकर मिश्र |**

तापमान, वर्षा और मिट्टी की नमी जैसे जलवायु कारकों में बदलाव का असर वनस्पतियों के फैलाव और उनकी वृद्धि पर पड़ता है। इन बदलावों के चलते भारत की विभिन्न नदी घाटियों के दो तिहाई हिस्से में मौजूद वन एवं कृषि क्षेत्रों में सूखे से उबरने की क्षमता कम हो रही है।

एक नए अध्ययन में भारतीय शोधकर्ताओं ने वर्ष 1982 से 2010 तक 29 वर्षों के तापमान, वर्षा और मिट्टी की नमी के आंकड़ों आधार पर एक सूचकांक तैयार किया है। इस सूचकांक का उपयोग वनस्पतियों पर जलवायु के प्रभाव को समझने के लिए किया जा सकता है।

इस सूचकांक से पता चला है कि देश की 24 में से 16 नदी घाटियों के कम से कम आधे हिस्से में मिट्टी की नमी का स्तर कम होने के कारण यह क्षेत्र सूखे से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। गंगा घाटी का सबसे अधिक क्षेत्र सूखे की संभावना से प्रभावित पाया गया है, जहां 25 प्रतिशत क्षेत्र सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील है।

## वनस्पति सूखे की संभावना और शुष्क स्थितियों के लिए लचीलापन

उत्तर-पश्चिम में स्थित माही, साबरमती और लूनी नदी घाटियों में भी सूखे का खतरा है। दक्षिण में पेन्नार घाटी का 96 प्रतिशत क्षेत्र मिट्टी की नमी कम होने पर सूखे से ग्रस्त हो सकता है। जबकि, कृष्णा, कावेरी और

तापी नदी घाटियों का 50 प्रतिशत हिस्सा सूखे के प्रति संवेदनशील है। इस अध्ययन में चरागाह, कृषि भूमि और प्राकृतिक वनस्पतियों सहित 10 वनस्पति प्रकारों को शामिल किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर के शोधकर्ता श्रीनिधि झा ने बताया कि "सूखे जैसी चरम जलवायु घटनाएं वनस्पति विकास को प्रभावित कर सकती हैं और सूखे की संभावना के चलते वानस्पतिक पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो सकता है। इसी कारण, बदलती जलवायु परिस्थितियों को केंद्र में रखते हुए हमने वनस्पति सूखे की स्थिति का आकलन किया है और जानने की कोशिश की है कि भारत के वनस्पति आवरण में जलवायु में किसी उथल-पुथल का सामना करने के लिए कितना लचीलापन है।"

शोधकर्ताओं ने बताया कि देश के कुल फसल क्षेत्र का दो-तिहाई हिस्सा वनस्पति सूखे के प्रति संवेदनशील है, जिससे खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। वनस्पति सूखे का अर्थ यहां जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी की नमी के स्तर में कमी से वनस्पतियों की वृद्धि एवं उनके वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव से है।

अध्ययन में शामिल शोधकर्ता डॉ मनीष गोयल ने बताया कि "अधिकतर नदी घाटियों के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में वनस्पति सूखे को सहन करने लिए लचीलापन नहीं है। इन क्षेत्रों में वनस्पति सूखा अधिक समय तक बना रह सकता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र खतरे में पड़ सकता है। सदाबहार वनों और फसल क्षेत्रों सहित प्रत्येक वनस्पति प्रकारों का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र सूखे को झेलने के लिए तैयार नहीं है।"

श्रीनिधि झा और डॉ मनीष गोयल के अलावा इस अध्ययन में आईआईटी, गुवाहाटी के आशुतोष शर्मा और बुधादित्य हज़रा शामिल थे। यह अध्ययन शोध पत्रिका ग्लोबल प्लेनेटरी चेंजेस में प्रकाशित किया गया है। ■

*( लेखक इंडिया साइंस वायर से जुड़े हैं।)*

# चक्रवाती तूफान फेनी से प्रभावित राज्यों में नीट की परीक्षा के आयोजन हेतु विकल्पों पर शीघ्र विचार हो : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केंद्र सरकार से चक्रवाती तूफान फेनी से प्रभावित राज्यों में नीट की परीक्षा के स्थगन की मांग की है। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम सहित कई तटीय राज्य चक्रवाती तूफान फेनी से बुरी तरह प्रभावित हैं तथा आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, ऐसे में छात्रों द्वारा इस परीक्षा में भाग लेना संभव नहीं है।

साथ ही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस परीक्षा का आयोजन फेनी से प्रभावित संबंधित राज्यों में किस प्रकार हो सकेगा, इस पर भी गंभीरता से विचार करे । या तो उन विद्यार्थियों को बाद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए अथवा उनके लिए उचित निवारण निकालते हुए उसे यथाशीघ्र राज्य सरकारों तथा आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, जिससे छात्र किसी भी असुविधा से बच सकें। उड़ीसा में पहले ही फेनी के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नीट की परीक्षा को स्थगित किया

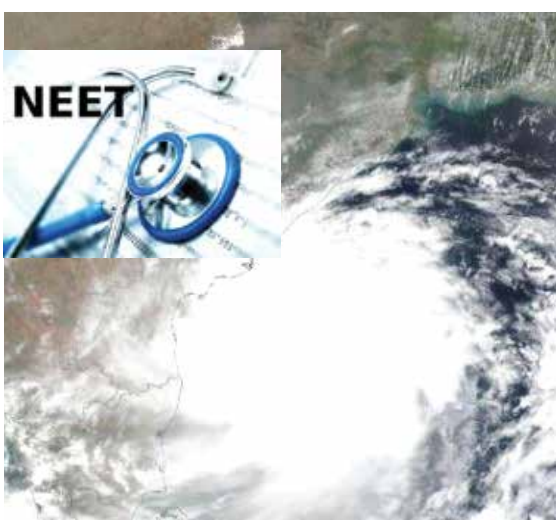


जा चुका है। इस कदम का अभाविप स्वागत करती है तथा केंद्र सरकार से अन्य राज्यों का आंकलन करते हुए अपेक्षित कदम उठाने की मांग करती है। ■

# एसिड हमले के खिलाफ़ एकजुट हो भारत

**| अभिषेक रंजन |**

एसिड अटैक की एक घटना से पूरा बिहार आक्रोशित है। घटना बिहार के भागलपुर की है, जहाँ एक घर में घुसकर कुछ अपराधियों ने इंटर में पढ़ने वाली पीड़िता लड़की से पहले छेड़छाड़ की कोशिश की, सफल नही रहने के बाद अपराधियों ने पीड़िता को तेजाब से नहला दिया। तेजाब हमले से जख्मी पीड़िता अभी तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अपराध की इस घटना के वक्त पीड़िता की मां भी घर में मौजूद थीं, मगर अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें रोके रखा और बेबस माँ सबकुछ अपने आँखों के सामने देखते हुए भी कुछ नही कर पाई। तेजाब हमले से पीड़िता के चेहरे समेत सीने और पेट के अधिकांश हिस्से बुरी तरह से जल गए, जिसका इलाज अभी वाराणसी के एक अस्पताल में चल रहा है जहाँ इन पंक्तियों के लिखते वक्त भी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई थी।

घटना के बाद पुलिसिया कारवाई में कुछ संदिग्ध पकड़े गए है, लेकिन अभी तक वह सबूत जुटाने में सफल नही रही है। इस घटना के बाद आम जनमानस में बेहद आक्रोश है और वे पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और दोषियों को पकड़ने एवं कड़ी सजा अविलम्ब देने की मांग की है। यही नही परिषद् के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के इलाज के लिए भिक्षाटन किया एवं तक़रीबन 50000 रुपये जुटाकर परिजनों को सौंपे।

केवल भागलपुर ही नही, देश भर के कई हिस्सों में एसिड अटैक की घटनाओं के होने की ख़बरें आये दिन आती रहती हैं। एसिड के हमलों से पीड़ित लोगों में अधिकांशतः महिलायें ही होती हैं। हमले के बाद उनके असहनीय दर्द और जख्म के निशान से हुए मानसिक प्रभाव का हम अंदाजा भी लगा सकते है। पहले एसिड अटैक से संबंधी कोई ठोस कानून न होने से सजा भी कम मिलती थी, वहीं पीड़िता भी हमले से हुए शारीरिक नुकसान को कम करने और महंगे इलाज के लिए जरुरी बंदोबस्त करने में असहाय की स्थिति में रहती थी।

नरेंद्र मोदी सरकार ने 16 दिसंबर 2016 को द राईट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी बिल-2016 के जरिये एसिड अटैक पीड़ित को भी दिव्यांग श्रेणी में रखा है ताकि उन्हें और अधिक सहायता मिल सकें। वहीं एसिड अटैक को लेकर देश में अब कानून भी सख्त है। इसके लिए आईपीसी की धारा 326 में भी बदलाव कर 326 A और 326 B जोड़ा गया है।

आईपीसी की धारा 326 A में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका और उसे स्थाई या आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया तो इसे एक गंभीर जुर्म माना जाएगा। अपराध गैर जमानती होगा। दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। 326 A में यह भी प्रावधान है कि दोषी पर उचित जुर्माना भी होगा और जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।

वही आईपीसी की धारा 326 B का संबंध एसिड अटैक के प्रयास से है। इस कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया है तो यह एक संगीन अपराध है। यह अपराध गैर जमानती है। इसके लिए दोषी को कम से कम पांच साल तक की सजा हो सकती है और दोषी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

यही नही वर्ष 2015 के अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने का भी एक महत्वपूर्ण निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को देते हुए कहा था कि वह ऐसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए विशेष कानून बनाएं। अटैक की शिकार महिला को इलाज और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान भी है, वहीं एसिड अटैक के मामलों में मुआवजा राशि सात लाख रुपए है। इस राशि को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (एनएलएसए) ने तय किया है।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की भाषा में कहे तो एसिड अटैक 'असभ्य और हृदयविहीन अपराध' है जो कतई क्षमा योग्य नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहद जरुरी है कि पूरा देश एकजुट होकर इस घृणित अपराध के प्रति समाज को संवेदनशील बनाये, साथ ही सरकार के साथ मिलकर तेजाब की खुलेआम बिक्री को नियंत्रित करें। एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग करने की भी बेहद आवश्यकता है। ■

# युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार : भुपेन्द्र नाग

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती पर रोक लगाने से युवाओं में काफी रोष है । अभाविप ने सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है । अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री भुपेन्द्र नाग ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ सरकार वचनभंग की अपराधी है । सरकार में आने के लिए ही नौकरियां सृजित करने का वचन दिया और सरकार में आते ही यह कहकर मुकर जाना कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के चलते 2014 से चली आ रही यह रोक पुनः एक साल के लिए बढ़ायी जा रही है, यह बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के साथ भद्दा मजाक है। ये छात्रों के साथ घोर अन्याय है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी घोर निंदा करती है। लोकसभा चुनाव तक वोट पाने की नियत से युवाओं को विभिन्न प्रकार के लोकलुभावन सपने दिखाए गए और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए भूपेश सरकार की असली नियत और नीति सामने आने लगी है। अभाविप भूपेश सरकार को आगाह करती है कि इस फैसले पर तुरंत रोक लगाए और छात्र हितों में फैसला ले नहीं तो जोरदार प्रदर्शन होगा ।

वहीं अभाविप छत्तीसगढ़ की प्रदेश मंत्री सन्नी केसरी ने कहा कि यदि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो उसे ठीक करने के लिए लोक लुभावन योजनाओं को बंद करने अथवा अनावश्यक सरकारी खर्चों पर लगाम कसने जैसे और भी कदम उठाए जा सकते हैं । आर्थिक संकट का हवाला देकर हताश युवावर्ग को अनिश्चितता के गर्त में धकेलना कहां तक उचित है ? सरकार के इस निर्णय ने नीति - नियंताओं की पोल - खोल कर रख दी है । अभाविप सरकार से यह मांग करती है कि वह अपने इस निर्णय को तत्काल वापस ले अन्यथा हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे । परिषद् बेरोजगारी को पुष्ट कर युवाओं को पस्त करने वाले सरकार के इस निर्णय के विरोध में प्रदेश के युवावर्ग के साथ है । ■

महात्मा गांधी की सार्धशती पर विशेष आलेख श्रृंखला - 8

# सभ्यतागत समझ और विभाजन की गुत्थी

**।डा. जयप्रकाश सिंह।**

सेमेटिक सभ्यताओं को समझने में भारतीय पिछली कई सदियों से लगातार चूक रहे हैं। हो यह रहा है कि भारतीय नेतृत्व अपनी सभ्यता के गुण-दोषों को दूसरी सभ्यताओं पर आरोपित कर कुछ सहज, मानवीय और उदात्त निष्कर्ष निकाल लेता है। इस पद्धति से निकलने वाला सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि सभी पंथ समान है और सभी धर्मों में शांति एवं भाईचारे की बात कही गई है। लेकिन जब भारतीय नेतृत्व का वास्ता अन्य सभ्यताओं की वास्तविकताओं से पड़ता है तो वह किंकर्तव्यविमूढ़ और बेबस हो जाता है। इस सभ्यतागत समझ की परिधि में ही गांधी और उनके चर्चित कथन - 'विभाजन मेरी लाश पर होगा' को सही तरीके से विश्लेषित किया जा सकता है।

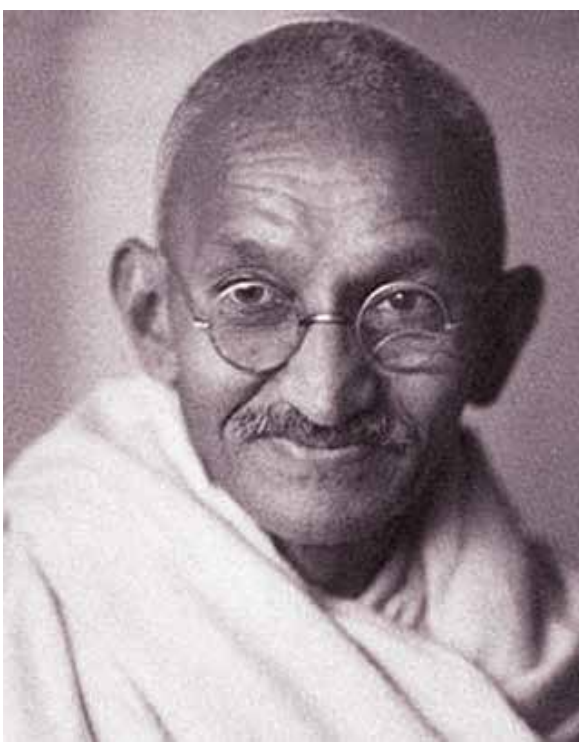

गांधी के इस कथन ने पूरे देश को आश्वस्त किया था कि विभाजन नहीं होगा, विभाजनकारी शक्तियों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। दुर्भाग्य से जब विभाजन ने यथार्थ रूप में दस्तक दी तो लाचारी के साथ गांधी ने उसे स्वीकार कर लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जब रोते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर पख्तूनों के साथ विश्वासघात किया है, तो प्रकारांतर से वे गांधी की ही विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे थे।

प्रश्न यह उठता है कि गांधी की चूक क्या व्यक्तिगत चूक थी, या पूरी भारतीय सभ्यता ही पांथिक समानता के सम्मोहन में अपनी जड़ें खोदने पर उतारू है। भारतीय पिछले हजार-बारह सौ सालों से यह रट लगाए हुए हैं कि सभी पंथ समानता और सह-अस्तित्व का संदेश देते है। लेकिन क्या सेमेटिक पंथों का भी यही दृष्टिकोण है?

जहां पर दिन में पांच बार इस बात की घोषणा की जाती है कि केवल उनका सच ही अंतिम सच है और उनके पैगम्बर ही सच के एकमात्र उद्घोषक हैं, वहां पर समानता और सह-अस्तित्व के लिए कितना स्पेस बनता है ? जिनकी विश्वदृष्टि दुनिया के पांथिक विभाजन पर निर्भर है और जहां पर अन्य मतावलम्बियों को पहले से ही जाहिल मान लिया गया हो, वहां पर शांति के लिए कितनी गुंजाइश बचती है ? जहां पर जन्नत में प्रवेश की संभावना दूसरों के सफाए के समानुपात में बढ़ती हो, वहां पर मानवीय दृष्टिकोण कैसे काम कर सकता है ? दुर्भाग्यवश, इन प्रश्नों से मुठभेड़ करने की हिम्मत भारतीय नेतृत्व लम्बे अरसे से नहीं जुटा पा रहा है। इसी कारण निर्णायक मौकों पर या तो हम औंधे मुंह गिरते हैं या हमें अपने पांव पीछे खींचने पड़ते हैं।

गांधी पांथिक समानता के नारे से कुछ अधिक ही सम्मोहित थे। वह असहयोग आंदोलन में भी खिलाफत

के प्रश्न को जोड़ते हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि भारत में तुष्टीकरण की राजनीति का प्रारंभ गांधी के खिलाफत आंदोलन से ही होता है। 1920 के बाद सार्वजनिक स्तर पर कई ऐसे मौके देखने को मिलते हैं, जहां गांधी मुस्लिमों को 'अतिरिक्त' देकर रिझाने की कोशिश करते हैं या हिंदुओं के वाजिब मांगों को भी साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील ठहरा कर उनकी चर्चा करने से भी परहेज करते हैं।

संभवतः वह यह मानते थे कि मुस्लिमों को 'अतिरिक्त' देकर उन्हें भारतीय मुख्यधारा में बनाए रखा जा सकता है। तुष्टीकरण के जरिए एक वर्गविशेष को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का यह प्रयोग गांधी से शुरू होकर अब तक जारी है। इस मृगमरीचिका से अब भी भारत का राजनीतिक प्रतिष्ठान निकल नहीं पाया है। इस प्रयोग के कारण कितने लोग मुख्यधारा में शामिल हुए, यह आकलन का विषय है लेकिन इसके कारण यह जरूर हुआ कि मुख्यधारा के ऊपर ही हाशिए पर जाने का खतरा मंडराने लगा। इसी मानसिकता से वशीभूत होकर कुछ लोग आज भी यह तर्क देते हैं कि यदि जिन्ना को 1937 के बाद उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया होता तो देश का विभाजन नहीं होता। ऐसे लोग उचित को परिभाषित करने की जहमत नहीं उठाते। उचित प्रतिनिधित्व की इस मांग का अंत क्या होता। शायद पहले वह देश का प्रधानमंत्री पद मांगते और बाद में देश ही मांगने लगते।

देश के विभाजन के साथ ही गांधी का कुछ अतिरिक्त देकर वर्ग विशेष को साथ जोड़ने का प्रयोग विफल हो गया था। देश ने इस प्रयोग की भारी कीमत चुकायी। इससे भी निराशाजनक तथ्य यह है कि इस प्रयोग की असफलता के कारण बहुत कुछ खोने के बावजूद 1947 के बाद भी राजनीतिक प्रतिष्ठान ने कुछ अतिरिक्त देने की नीति को जारी रखा बल्कि उसे अति की सीमा तक पहुंचा दिया गया। इसकी अति शाहबानो केस में तो देखने को मिली ही थी, संप्रग शासनकाल में प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक में इस तुष्टीकरण की नीति की अति देखी जा सकती है। इस विधेयक का लब्बोलुआब यह था कि अपराध कोई भी करे, दोषी हिंदू ही होगा।

गांधी ने अपने सार्वजनकि जीवन में कई प्रयोग किए। कुछ सफल हुए और कुछ असफल। एक तथ्य तो एकदम स्पष्ट है, वह पांथिक समानता के मोर्चे में उनकी समझ और प्रयोग दोनों बुरी तरफ असफल हुए। भारतीय राजनीतिक प्रतिष्ठान जितनी जल्दी यह मान ले कि पांथिक सह-अस्तित्व का लक्ष्य गांधी के रास्ते पर चलकर नहीं प्राप्त किया जा सकता, भारत और भारतीयता को होने वाला नुकसान उतना ही कम होगा।

यहां पर प्रश्न यह भी उठता है कि फिर पांथिक सह-अस्तित्व के संभावित रास्ते क्या होंगे? इतना तो कहा ही जा सकता है कि कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। रास्ता पहचानने और रास्ते पर आने के लिए हमें सभी सभ्यताओं की एक निभ्रांत समझ विकसित करनी होगी। यदि कुछ असुविधाजनक तथ्य हैं तो उन्हें स्वीकारना होगा, उन्हें कहना-बताना होगा। तथ्यों के कठोर धरातल पर ही रास्ते बनते-बिगड़ते हैं। हवाई किले बनाने की आदत के कारण यह देश पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। सभ्यतागत प्रेरणाओं-प्रतिक्रियाओं को ठीक ढंग से समझने की चुनौती को हमें स्वीकार करना ही होगा। गांधी इस कार्य में अवरोधक नहीं बनेंगे, न ही उन्हें अवरोधक बनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रयोगधर्मिता गांधी की सबसे बड़ी विशेषता है। ■

*(लेखक हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।)*

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' मई 2019 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

# साहसी फिल्म 'द ताशकंद फाइल्स' जिसे दस साल पहले बनाना नामुमकिन था

| आशीष कुमार 'अंशु' |

'बुद्धा इन ट्रैफिक जाम' फिल्म में विवेक अग्निहोत्री की पहचान एक ऐसे फिल्मकार की बनी जो लीक से हटकर फिल्म बना रहे थे। लीक से हटकर का अर्थ यहां उस गिरोह से हटकर है, जो वॉलीवुड पर दशकों से राज कर रहा था। वहां खास तरह की फिल्म बनती थी। एक खास नैरेटिव के साथ, निश्चित तौर पर उस वक्त एक खास तरह का एजेन्डा फिल्म के माध्यम से प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती थी। जहां एक खान चाचा होते थे, पांच वक्त के पक्के नमाजी। जो बेहद ईमानदार होते थे। वहीं एक चुटिया वाला पंडित होता था जो मंदिर में आने वाली लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। बहरहाल, अब बॉलीवुड बदल रहा है। वहां की फिल्मों की कहानियां बदल रही है। आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही थी, आज से दस साल पहले कांग्रेस की सरकार में विवेक जिस तेवर की फिल्म बना रहे हैं, वैसी फिल्म बनाना नामुमकिन जैसा था।

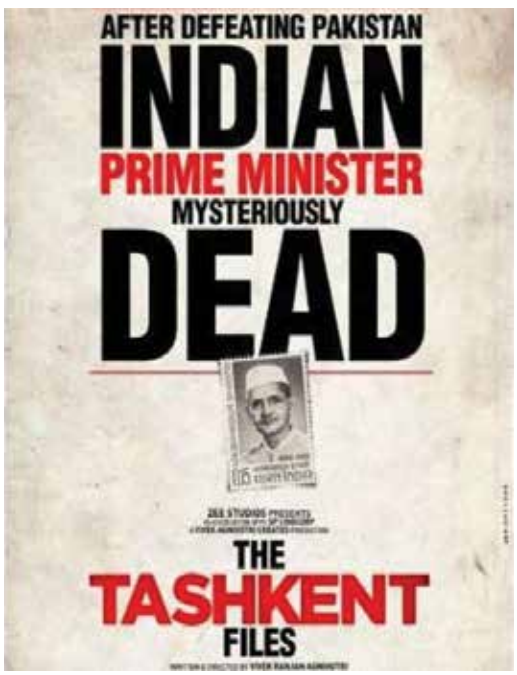


'द ताशकंद फाइल्स' में विवेक ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के इर्द गिर्द बुनी है। यह सब दिखा पाना यदि आसान होता तो यह फिल्म दशकों पहले बन चुकी होती। अब यह फिल्म शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु का किस्सा दोबारा देश के सामने रखती है। फिल्म आज के समय को दर्शाती है जिसके लिए फिल्म की किरदार रागिनी फुले जो एक महत्त्वाकांक्षी पत्रकार है के आस—पास फिल्म की कहानी चलती है, जो एक बड़ी खबर की तलाश में है। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत का रहस्य वह जानने की कोशिश करती है और ताशकंद फाइल्स के हवाले से वह सच जान भी लेती है।

वह ताशकंद फाइल्स के आधार पर अपनी खबर लिखती है और अखबार में खबर छपने के बाद खबर की खासी चर्चा होती है। जिसके चलते सरकार पर दबाव पड़ता है और सरकार को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का केस दोबारा खोलना पड़ता है। फिल्म में रागिनी फुले का किरदार श्वेता बसु प्रसाद ने अदा किया है। शास्त्री जी की मृत्यु से परदा हटाने के लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति में मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, पल्लवी जोशी, पंकज त्रिपाठी, मंदिरा बेदी, राजेश शर्मा हैं।

सभी के उम्दा प्रदर्शन ने फिल्म में जान डाली है। मंदिरा बेदी ने भी काफी अच्छी एक्टिंग दिखाई है। जासूस के किरदार में विनय पाठक कहानी की अहम

"द ताशकंद फाइल्स" के नाम से ही मन में यह उत्सुकता आती है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भूमिका, उनकी रहस्यमय मृत्यु और तत्कालीन घटनाक्रम के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। यह उत्सुकता ही थी जिसने मुझे इस फिल्म को देखने के लिये प्रेरित किया। श्री शास्त्री के जीवन के अंतिम क्षणों को समेटने वाले इस चित्रपट में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

चित्रपट को देखने के बाद जो नये तथ्य और विवरण सामने आते हैं, वह जानना देश के हित में आवश्यक है। दिखाये गये घटनाक्रम से जुड़े अनेक पहलू हमें गहराई से विचार करने के लिये प्रेरित करते हैं। चित्रपट यह रेखांकित करता है कि अगर हम देश और समाज के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो षड्यंत्र इसी प्रकार चलते रहेंगे। राजनीति स्वार्थों को पूरा करने वाली बनी रहेगी।

कथानक के साथ ही फिल्म का तकनीकी पक्ष और कलाकारों का अभिनय उत्कृष्ट है। युवा पीढ़ी को जाग्रत करने के लिये इतिहास की सही जानकारी, श्री लालबहादुर शास्त्री के गौरवपूर्ण जीवन और रहस्यमय मृत्यु के बारे में जानकारी की दृष्टि से यह चित्रपट महत्वपूर्ण है। निर्देशक ने तथ्यों से छेड़-छाड़ न करते हुए कलात्मक ढ़ंग से समूचे घटनाक्रम को परदे पर सजीव कर दिया है। निश्चय ही यह एक सार्थक प्रयास है जिसे सबको अवश्य देखना चाहिये।"

— **मा. मोहन राव भागवत**, सरसंघचालक रा. स्व. संघ

कड़ी बनते हैं। पंकज त्रिपाठी तो हैं ही सबसे अलग। फिल्म का डायरेक्शन सराहनीय है। आधे से ज्यादा समय एक छोटे से सरकारी दफ्तर में शूट हुई यह फिल्म आपको अपने नाखून चबाने के लिए मजबूर कर देगी।

फिल्म की कहानी को पुख्ता करने के लिए कई तरह के रशियन स्पाई एजेंसी यानी केजीबी के पुराने दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने जिस नए तरह की कहानियों को कम बजट में प्रस्तुत करने का प्रयोग किया। वह नए निर्माताओं को प्रभावित कर रहा है। कलंक जैसी फिल्म के सामने रिलीज हुई द ताशकंद फाइल्स उसे पीटती हुई आगे निकल गई। इस फिल्म की कथित निष्पक्ष पत्रकारों ने जिस तरह समीक्षा की उसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहा जाना लगा कि कांग्रेस पोषित पत्रकारों को फिल्म पसंद नहीं आ रही। इसका मतलब फिल्म में जरूर कुछ खास है। इस फिल्म में विवेक दर्शकों को निराश नहीं करते। यह सच है कि जिन दस्तावेज़ों का फिल्म में प्रयोग किया गया है, उसी पर आखिर में कहा जाता है कि यह सभी दस्तावेज पुख्ता तौर पर नहीं माने जा सकते लेकिन इस तरह कलात्मक स्वतंत्रता हमेशा से कला माध्यम में ली जाती रही है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जिस शास्त्री को लोग भूलने लगे थे, उन्हें अचानक फिर से द ताशकंद फाइल्स ने समाज के बीच प्रासंगिक बना दिया। ■

# गंभीर खतरे की आहट है श्रीलंका आतंकी हमला

**मुकेश कुमार सिंह**

श्रीलंका लिट्टे के साथ गृहयुद्ध की समाप्ति के एक दशक बाद भीषण आतंकी हमले से दहल गया। इस आतंकी हमले से, अतिवादी संगठन लिट्टे के खात्मे के बाद शांति और स्थिरता की ओर बढ़ रहे श्रीलंका की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। 21 अप्रैल को हुए 8 सिलसिलेवार आतंकी बम धमाकों में 253 लोगों की मौत हुई जबकि 500 सौ से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च और पश्चिम तटीय शहर नेगोंबे के सेंट सेबेस्टियन चर्च को अपना पहला निशाना बनाया। इसके बाद कोलंबो के तीन होटलों और बट्टीकलोआ के एक चर्च में धमाका हुआ। दोपहर बाद दो बम धमाके कोलंबो के चिड़ियाघर के पास हुए। ईस्टर ईसाईयों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और यह आतंकी हमला ईसाई समुदाय को ध्यान में रखकर किया गया है। इस हमले में श्रीलंका को कितना नुकसान हुआ है इसका हिसाब तो बाद में लगाया जाएगा लेकिन आतंकियो ने ईसाई समुदाय को ध्यान में रखकर चर्च और होटलों पर हमला करके यह जता दिया है कि उनका इरादा क्या है। इस आतंकी हमले से दशकों से आतंकी गतिविधियों से त्रस्त दक्षिण एशिया में शांति की पहल की उम्मीद को भी बड़ा झटका लगा है।

श्रीलंका में करीब तीन दशकों की राजनीतिक अस्थिरता के बीच वहां का समाज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में विभाजित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सिंहलियों और तमिलों के बीच कई बार जातीय संघर्ष हुए। श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहली 70 प्रतिशत, श्रीलंकाई एवं भारतीय तमिल 13 प्रतिशत, मुस्लिम 10 प्रतिशत, ईसाई 7 प्रतिशत हैं। बहुसंख्यक सिंहली बौद्ध धर्म और तमिल हिन्दू धर्म के अनुयायी है। यह हमला जातीय नहीं बल्कि साम्प्रदायिक था, जिसमें मुस्लिम चरमपंथियों ने ईसाईयों को निशाना बनाया। आतंकियों के निशाने पर भारतीय उच्चायोग भी था, परन्तु उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण वे असफल रहे। यह आतंकी हमला श्रीलंका के लिए एक बड़ी त्रासदी तो है ही भारत के लिए भी एक गम्भीर चुनौती है। श्रीलंका को दहलाने वाले आतंकी हमले से भारत का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह कि हमला एक ऐसे पड़ोसी देश में हुआ है, जहां हमारे गहरे हित निहित है। दूसरा कि हमले को अंजाम देने वाले आइएस समर्थित मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) का संबंध पूर्व में तमिलनाडु से जुड़े होने का अंदेशा है। इस आतंकी

संगठन के सरगना का तमिलनाडु में आना-जाना था और उसे दक्षिण भारत से बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता मिलती रही।

इस हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती आतंकी संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि के पढ़े लिखे लड़के थे, इसमें से एक आस्ट्रेलिया में भी रह चुका था। घटना को श्रीलंका के मसाला कारोबारी के दो बेटों समेत नौ कुख्यात आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला आतंकी भी शामिल थी। पुलिस अब तक 106 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें तमिल का एक शिक्षक और स्कूल का एक प्रिंसिपल भी

शामिल है। हालांकि इस सिलसिलेवार आतंकी हमले की जिम्मेदारी कुख्यात कट्टरपंथी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ली है। उसने ट्वीट कर काले कपड़े पहने हुए आठ आत्मघाती आतंकियों की तस्वीर जारी की है, तस्वीर में उनकी पहचान अबु उबैदा, अबु अल-मुख्तार, अबु खलील, अबु हमजा, अबु अल-बारा, अबु मोहम्मद और अबु अब्दुल्ला के रूप में हुई है। जारी की गई तस्वीर में नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) का प्रमुख मोहम्मद जहरान हासिम (उबैदा) भी दिखाई दे रहा है। हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन का सरगना मोहम्मद जहरान पांच सितारा होटल शंगरी-ला विस्फोट में मारा गया।

श्रीलंकाई रक्षा राज्य मंत्री रुवान विजयवर्धने ने संसद में कहा कि यह वीभत्स आतंकी हमला न्यूजीलैंड स्थित क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया हो सकता है। 15 मार्च, 2019 को न्यूजीलैंड में एक ईसाई सिरफिरे ने क्राइस्टचर्च की मस्जिद में 49 नमाजियों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। आइएस और उसके समर्थित आतंकियों ने ईसाईयों पर हमले कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय खास तौर से पश्चिमी देशों को अपनी उपस्थिति का संदेश दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन ने हमले के लिए जिम्मेदार आइएस से संबंधित स्थानीय मुस्लिम चरमपंथी आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) और जमातेई मिलातू इब्राहिम (जेएमआइ) पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। हमले में शामिल आतंकियों की संपत्तियों की पहचान कर जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। आतंकी हमले के एक सप्ताह बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति सिरिसेना ने सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सभी तरह के परिधानों पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे किसी शख्स के पहचान में परेशानी होती है। राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया है कि 'यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है.... किसी को अपना चेहरा ढककर अपनी पहचान मुश्किल नहीं बनानी चाहिए।' सरकार के इस फैसले का असर बुर्का और नकाब पहनने वाली महिलाओं पर भी पड़ेगा।

श्रीलंका में हुआ आतंकी हमला अत्यधिक दुःखदायी है लेकिन उससे भी ज्यादा निंदनीय है उसे लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार। वैश्विक मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इसे क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया बताता है। जबकि सच तो यह है कि विश्व में एक वर्ग ऐसा है जो इस हमले को प्रतिरोध की कार्रवाई बताकर मज़हबी आतंकवाद के मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहता है। इसी तरह एक भारतीय वामपंथी ने श्रीलंका बम धमाकों को लेकर किए गए ट्वीट में 'बौद्ध कट्टरवाद' को हाइलाइट करते हुए कहा कि 'भले ही इसमें उनका हाथ हो या न हो, ये ब्लास्ट्स मालेगांव की तरह हैं।' भारतीय मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने इस धमाके में सिंहलियों और तमिलों का हाथ बताया, लेकिन जैसे ही आतंकी संगठन आइएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, वे गायब हो गए।

दक्षिण एशिया में अशांति का सबसे बड़ा कारण आतंकी गतिविधियां है और भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां पहले से ही भारत की चिंता का कारण है तब पड़ोसी देश श्रीलंका में आइएस और नेशनल तौहीद जमात की उपस्थिति भारत की इस चिंता को और बढ़ाने वाली है। श्रीलंका में हमले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने केरल के दो युवाओं अबू बकर सिद्दिकी और अहमद अराफात को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि इन युवाओं का सीधा संपर्क श्रीलंका हमले के मुख्य साजिशकर्ता जहरान हाशिम से है। श्रीलंका की घटना कोई छिट-पुट मामला नहीं है यह तो एक बानगी है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां श्रीलंका में सीरियल बम धमाकों से जुड़े आत्मघाती हमलावरों में से एक अब्दुल लतीफ जामील मोहम्मद और ब्रिटेन के चरमपंथियों के बीच संबंधों की जांच कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त चौकसी बरतने की जरूरत है। इस जरूरत की पूर्ति के लिए सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनानी होगी। आतंकी हमले की इस त्रासदी के बाद श्रीलंकाई सरकार और उसके नागरिक समाज को जल्द ही इस संकट से उबारने के लिए विश्व समुदाय को हर संभव मदद करनी चाहिए। विश्व के राजनीतिक मंच और दक्षिणी एशिया में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसके लिए जरूरी है कि वह पड़ोसी देशों को विश्वास में लेकर आतंक के खिलाफ एक समग्र एवं दीर्घकालीन योजना का नेतृत्व करे। ■

*(लेखक जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र से जुड़े हैं)*

# श्रीलंका में निरंतर हुए आत्मघाती हमलों में सैकड़ों नागरिकों की मृत्यु बेहद दुर्भाग्यपूर्ण: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में कई दिनों से लगातार चल रहे बम धमाकों में मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति श्रद्धांजलि तथा उनके परिवारों के प्रति सांत्वना की गई है। अभाविप का मानना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तथा बर्बर घटना है।

श्रीलंका में अलग अलग स्थानों पर सिलसिलेवार रूप हुए बम विस्फोट बेहद पीड़ादायी है । गौरतलब है कि इन बम धमाकों में लगभग 350 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा 500 से अधिक लोग घायल है। हाल ही के कुछ महीनों में विश्व के कई राष्ट्रों में लगातार ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि विश्व बंधुत्व एवं शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुकी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि ऐसे में सभी राष्ट्रों को विश्व से आतंकवाद के खात्मे के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है।

श्रीलंका में हुए हमले की निंदा करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने कहा कि, "हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में इस तरह का हमला बेहद निंदनीय एवं बर्बरतापूर्ण है, हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं तथा समूचे विश्व से यह आगाह करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों, जिससे विश्व में शांति व स्थिरता स्थापित हो सके।" ■

# अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का निधन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. कल्याणब्रत भट्टाचार्य का 22 अप्रैल 2019 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान में निधन हो गया । डॉ. भट्टाचार्य के निधन की खबर सुनते ही अभाविप के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई । डॉ. कल्याणब्रत पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं । पश्चिम बंगाल में विद्यार्थी परिषद् के कार्यों का व्यापक रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । डॉ. कल्याणब्रत भट्टाचार्य के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में अभाविप ने कई बड़े आंदोलन किये हैं । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । अभाविप ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. कल्याणब्रत सर के निधन से परिषद् को अपुरणीय क्षति हुई है, शिक्षा में उनकी रिक्तता को भर पाना संभव नहीं है । दुःख की इस घड़ी में परिषद् का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉ. भट्टाचार्य के परिवार के साथ खड़ा है । उनका पार्थिक शरीर भले ही हमलोगों के बीच नहीं है लेकिन उनका विचार हम सबों को सदैव प्रेरित करती रहेगी । बता दें कि डॉ. भट्टाचार्य बर्दवान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे । बाल्यकाल से ही उनका झुकाव राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ थी । ■

# 'वसुधैव - कुटम्बकम्' को चरितार्थ करता विश्व विद्यार्थी युवा संगठन (WOSY)

'वसुधैव - कुटम्बकम' - भारतीय संस्कृति के चिंतन का मूल आधार है, इस महान दृष्टि को केन्द्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा एक प्रकल्प, विश्व विद्यार्थी युवा संगठन (WOSY) का शुभारंभ दिल्ली से किया गया । परिषद् को कहां पता था कि देखत ही देखते WOSY विशाल वटवृक्ष का रूप ले लेगा । पूर्व में WOSY के सेक्रेटरी जनरल रहे अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रमेश पप्पा बताते हैं कि 1985 में जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की गई तब ध्यान में आया कि वैश्विक स्तर पर युवाओं के बीच काम करने वाला एक मंच होना चाहिए जो दुनिया के युवाओं/छात्रों को एक मंच पर लाकर दुनिया की बेहतरी और जीने लायक बनाने के लिए काम करे । इन सब बातों को ध्यान में रखकर अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिल्ली के राजघाट के पास हुआ था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी आये थे । उनकी उपस्थिति में विश्व विद्यार्थी युवा संगठन WOSY का शुभारंभ हुआ । भारत में पढ़ने वाले विभिन्न देशों के हजारों विद्यार्थियों के साथ उनकी समस्याओं को जानना, उनका सहयोगी बनकर उन्हें एक ऐसा मंच देना जहां से वह राजनैतिक एवं आर्थिक स्वार्थ, भौतिकवादी विचारधाराओं से मुक्त होकर पूरी दुनिया के युवाओं को दूसरे राष्ट्रों की आध्यात्मिक अनुभूति और मानवता के आधार पर देख सके। उन्होंने बताया कि भारत में पढ़ रहे छात्रों के साथ WOSY के द्वारा दीपावली, होली या अन्य प्रकार के मिलन समारोह को आयोजित कर भारत की संस्कृति से परिचित करवाना, प्रारंभ में WOSY का मूल कार्य था । धीरे - धीरे WOSY की व्यापकता बढ़ती गई फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सम्मेलन, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया जाने लगा। 2006 से 2009 तक मैं WOSY का सेक्रेटरी जनरल था उस दौरान बैंगलोर में इंटरनेशनल टेररिज्म पर बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व भर के युवाओं ने बढ़ - चढ़कर भाग लिया था । इसी तरह मुंबई, दिल्ली आदि जगहों पर भी कई आयोजन हुए ।

वहीं WOSY की चेयरपर्सन श्रीमति रश्मि सिंह बताती हैं कि विश्व में WOSY एक मात्र ऐसा फोरम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है । वर्तमान में WOSY के साथ 10 हजार से अधिक विदेशी छात्र जुड़कर विश्व के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं । WOSY एक ऐसा फोरम है जो समय - समय पर विश्व के समसामयिक मुद्दों, शोध, शिक्षा, अकादमिक सुधार इत्यादि पर कार्यशाला, संगोष्ठी का आयोजन करती हैं । उन्होंने कहा कि WOSY में मुख्यतः दो प्रकार की गतिविधि चलती है पहला - शुद्ध अकादमिक और दूसरा हेल्प डेस्क जैसा । इसी साल जनवरी 2019 में ओड़िसा के भुवनेश्वर में हमलोंगो ने The 21st Century Women's Issues Shaping the World विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के युवाओं ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, प्लानरी इत्यादि पर कुल सात सत्र का आयोजन किये गये थे । संगोष्ठी का उदघाटन ओड़िसा के राज्यपाल ने किया । संबंधित सत्रों में उस क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे, जो विश्व के विभिन्न भागों से आये थे। सत्र में छात्रों ने पहले अपना अभिकल्प ( पेपर ) जमा किये फिर उस पर चर्चा का आयोजन हुआ। विशेषज्ञों ने छात्रों के शंकाओं का समाधान किया। उसके बाद उनके अभिकल्प को अंतिम रूप से जमा लिया गया । बकौल रश्मि सिंह अकादमिक सेशन के पहले समग्रता से इसकी रचना की जाती है। रचना के बाद उस पर चर्चा/बहस होती है । उन्होंने बताया कि छात्रों को WOSY के रूप में एक ऐसा मंच उपलब्ध है जहां पर वे अपनी प्रतिभा का पोषण कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती जो उन्हें कॉलेजों में नहीं मिलती लेकिन WOSY में आसानी से मिल जाते हैं, जिस कारण छात्र WOSY के आयोजनों को गंभीरता से लेते हैं। अकादमिक गतिविधि के अलावा

॥ वसुधैव कटुम्बकम् ॥
WORLD IS A FAMILY

हम भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रो के लिए हेल्प डेस्क का काम करते हैं। WOSY के माध्यम से विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मूल्यों का आदान - प्रदान हो रहा है । छात्र को हम भारतीय मूल्य, संस्कृति, इतिहास से अवगत कराते हैं एवं उनके देश के संस्कृति, इतिहास, जीवन मूल्य को जानने की कोशिश करते हैं। विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों से अवगत होतें हैं । अभी WOSY से 57 देशों के छात्र जुड़े हैं । देश भर में WOSY के कुल 15 चैप्टर हैं, देश में जहां - जहां विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर हमारा चैप्टर है। ओस्मानिया विश्वविद्यालय में विदेश छात्र महोत्सव का नेतृत्व हमारे WOSY के छात्रों ने किया । WOSY पूर्णतः गैर राजनीतिक मंच है जो विविधताओं से भरा हुआ है । नेपाल, अफ्रीका, कीनिया, श्रीलंका आदि देशों में WOSY के एल्यूमिनी अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता कि भारतीय दूतावास विदेशी छात्रों की जानकारी के लिए विश्व विद्यार्थी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं। कुल मिलाकर कहें तो WOSY सही मायने में भारतीय दर्शन 'वसुधैव - कुटम्बकम्' की संकल्पना को साकार कर रही है । ■

# WOSY celebrates Womanhood by recognizing them as powerful Transformative Agent for Global Harmony and Governance 2.0

World Organization of Students and Youth (WOSY) organized a panel discussion titled 'Women as Transformative Agent for Global Harmony and Governance 2.0' on International Women's Day at Satyakama Bhavan, Delhi University. Foreign Students from 10 countries made presentation dwelling into the topic and documenting their experience on Women as Transformative Agent. The students representing student from 20 nations participated.

The program was attender by nearly 150 foreign students. Prof. Neeta Sehgal, Proctor, Delhi University observed that women have always played pivotal role in social, political and academic life.

Ms. Aarti Bangia, a bureaucrat at Ministry of Commerce elucidated that women has become the focal point of the whole development process. The development agenda needs to made more gender sensitive. Also, the economic empowerment of women is a pre-requisite for overall development of society. Ms. Bhawna Rajpal, GM, Schneider Electric pointed out that women's role in families is often ignored. Almost 70% decision in houses are taken by women, but it is seldom acknowlegded.

Dr. Abhishek Tandon, Chairperson, WOSY Delhi Chapter on the occasion of international women's day addressed the foreign students from over 20 countries. He said 'India is a peace loving country and is not at war with any country but terrorism. He further said India is badly affected by terrorism sponsored by neighboring state and seek cooperation from global community to eradicate terrorism. Wosy believes in vasudhaiva kutumbhkan world is one family and welcome students from all the world to our country . Women are playing key role in all walks of life and it's an excellent opportunity to make our women feel special on this day.' WOSY is affiliate workshop with foreign students. Students from around 20 countries participated in women's day celebrations. Other speakers included Prof Neeta Sehgal , Proctor, University of Delhi , Ms Arti Bangi , Deputy Director Ministry of Commerce and Ms Bhawna Rajpal, GM , Schneider Electric.

Dr. Abhishek Tandon, observed that the isssue of recognizing Women as a Transformative Agent will bring about a fundamental and monumental shift in resolving and approaching global problems in a more nuanced manner. Abhijeet Dwivedi, International Secretary, WOSY stressed that WOSY has been engaging with the globe through the foreign students who will be decision-makers of future and has been trying to arrive at a consensus about future course of through a series of activities over the last 5 years. ■

# Think India organised CHANDIGARH DIALOGUE

Think India is an Initiative to bring together the best talent of this country and to infuse them with nation first attitude. It is a collective endeavor of creative minds free from all burdens and prejudice, dedicated to the cause of nation building. Think India is a forum of students from premier institutes like IIT, IIM, IISC, and National Law University and other such premier institutes in the various field of academia, across India. We organize events, workshop, seminars, study circles and conventions on National & Regional level involving participation of students at different level.

A Talk for New India in the name "Chandigarh Dialogue" was held at Hotel Shivalik Chandigarh. The theme for the dialogue was to differentiate between Education for Life and Skill Development for Employment. The daylong event Comprised of three vigorous Sessions. A total of seven eminent speakers of different expertise contributed to the Dialogue. A vibrant participation of audience comprising of distinguished guests, academicians, policy makers, professionals, young entrepreneurs and youth leaders enriched the dialogue.

In the first session, three main speakers were Dr.Unnat Pandit ( Head of Operations, Atal Innovation Mission, Niti Aayog), Dr.Ashwin Johar (Chairman, India Russia Bilateral Council, Niti Aayog) and Sr.Adv. Chetan Mittal (Assistant Solicitor General of India). They collectively delved to opine that Education is for learning to LIVE a life NOT for learning to EARN A LIVING for life. Professional qualification or Skill Development is recognized as a source for earning a living for life.

In the second session, Sh.Shantanu Gupta ( Author & Political Analyst), Dr. Gaurav Maheshwari (world renowned Gastroenterologist) Ms.Komal Talwar Sharma (Founder and Director of TT Consultancy) and Mr.Deepak Mukhija ( North Sales Head, DLF) remarked and highlighted the Government of India's sincere endeavour to differentiate between Education and Skill Development by creation of a separate Ministry of Skill Development from Ministry of Human Resource Development. As a result, New avenues of employment and changing trends in private sector have evolved. Ms. Komal Talwar said that in changing trends of work culture, gender bias is also mitigating.

In the third session, Sh.Vikrant Khandelwal (Noth Zone Organizing Secretary, ABVP), Sh.Vinit Goenka (TV Debator and Former Task Force Menber Ministry of Road Transport) and Ms.Nidhi Tripathi (National Secretaty, ABVP) highlighted the role of youth in Policy formulation for New India. They elaborated the aspiration of youth which comprises 70% of India population. It was emphatically laid that the policies should be based on the realistic ground data and research for their success. ■

# अभाविप ने किया तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) के खिलाफ प्रदर्शन

जिसे ऊंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी खुशी को जिसके सपनों में जोड़ दिया, जिसकी पढ़ाई के लिए मुसीबतों के पहाड़ को उठाया, कहां ! पता था कि वही पढ़ाई एक दिन मेरी आंखो की रौशनी छिन लेगा, मेरा चिराग बुझा देगा.....ये बातें आजकल तेलंगाना के अभिभावकों के मुंह से बरबस निकल जाता है । दरअसल, तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) ने 18 अप्रैल को कक्षा दशवीं और बारहवीं की परीक्षा परिणाम घोषित किये, परिणाम जारी होने के सप्ताह भी नहीं बीते थे हताश होकर छात्रों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया । मात्र 7 दिनों के भीतर 19 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। बताया जाता है कि इस बार उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में काफी गलतियां की गई थी, जिसकी वजह से छात्रों को उनकी प्रतिभा के अनुसार अंक नहीं मिले। तेलंगाना बोर्ड ने इस साल परीक्षा के लिए पंजीयन से लेकर परिणाम जारी करने की पूरी जिम्मेजदारी एक प्राइवेट फर्म ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज (Globarena Technologies) को दे दी थी । छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि फर्म की प्रणाली ने हमारे बच्चों को छिन लिया । बोर्ड की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं 12 वीं फेल हुए एक विद्यार्थी, गज्जा नाव्या को तेलुगू विषय में 0 अंक प्राप्त हुए थे। नाव्या ने अपना तेलुगू विषय को री इवैल्यूएशन के लिए दिया। री - इवैल्यूएशन करने पर नाव्या को जिस विषय में 0 अंक दिखाया गया था, उसमें 99 अंक मिले। नाव्या का मामला इस संदेह को मजबूत करता है कि परीक्षा परिणाम तैयार करने में कई गड़बड़ियां हुई है।

हैदराबाद में तेलंगाना के इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने लगातार कई दिनों तक प्रदर्शन कर जांच की मांग की। अभाविप का आरोप है कि छात्रों ने इंटरमीडिएट बोर्ड की गलतियों की वजह से आत्महत्या की है । सरकार ने पंजीयन से लेकर परिणाम तक की पूरी जिम्मेदारी एक प्राइवेट फर्म ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज (Globarena

## अभाविप की मांगें –

1. परिणामों का पर्याप्त डेटा विश्लेषण किया जाना चाहिए। परिणामों में पाई जाने वाली विसंगतियां, एक छात्र की तरह, जिसने पहले वर्ष में उच्च अंक प्राप्त किए और अगले वर्ष में असफल हुए या कम अंक प्राप्त किए, उन्हें इस तरह के प्रश्नपत्रों की पुनरावृत्ति के माध्यम से जांच करनी चाहिए।
2. आरवीआरसी सर्वर के साथ समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को तुरंत हल किया जाना चाहिए। यदि सर्वर के साथ समस्याएं हैं, तो समस्याओं को हल करने के लिए मैनुअल सिस्टम को तैनात किया जाना चाहिए।
3. ऐसे महत्वपूर्ण समय में छात्रों और अभिभावकों के लिए आईवीआर आधारित हेल्पलाइन की तैनाती की जानी चाहिए ताकि उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाए।
4. छात्रों की शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म **TSBIE** वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रावधान से छात्रों को उनकी समस्याओं को तेजी से और पारदर्शी तरीके से हल करने में बहुत लाभ होगा।
5. मौजूदा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को उन सभी उम्मीदवारों के पुनर्पूजीकरण के लिए तैनात किया जाना चाहिए जो रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि, एक स्वतंत्र एजेंसी को प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो परिणाम को स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समानांतर रूप से संसाधित किया जाना चाहिए ताकि आगे देरी का कारण न हो।
6. पूरक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी मॉड्यूल **TSBIE** अधिकारियों की देखरेख में हो । यदि त्रुटियां पाई जाती हैं, तो परेशानी मुक्त परीक्षा प्रक्रिया के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया या तो मैनुअल या स्वचालित लागू की जानी चाहिए।
7. इंटर बोर्ड के विघटनकारी शिक्षा मंत्री जगदीश्वर रेड्डी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे ।
8. सभी उत्तरपुस्तिकाओं को स्वतंत्र रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
9. ग्लोबरीना कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए और ग्लोबिना के स्वामी पर कार्रवाई हो।

Technologies ) को दे दी, कंपनी की लापरवाही एवं त्रुटिपूर्ण जांच के कारण आज दो दर्जन से अधिक छात्रों ने मौत को गले लगा लिया । हमारी मांग है कि सरकार इस पर संज्ञान लें और संबंधित दोषियों पर कठोर कार्रवाई करें साथ ही छात्रों की हितों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लें ताकि छात्रों का भविष्य व समय बर्बाद न हों । अभाविप छात्रों से भी अपील करती है आप धैर्य रखें । हताश होकर मौत को न चुनें, परिषद् आपके साथ है । मामले को लेकर अभाविप का एक शिष्टमंडल तेलंगाना के राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हन से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की । राज्यपाल नरसिम्हन ने अभाविप की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की । प्रतिनिधिमंडल में अभाविप के प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रसाद गारो, प्रदेश मंत्री अंबाला किरण, ग्रेटर हैदराबाद नगर मंत्री पगदीपल्ली श्रीरही आदि थे । ■

# देश को अस्थिर करने वालों का चेहरा उजागर हुआ : चौहान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में माओवादियों द्वारा देश की सुरक्षा में लगे जवानों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करती है । अभाविप शहीद जवानों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करती है तथा उनके परिवारों के प्रति संवदेना प्रकट करती है । देश में आम चुनावों के दौरान इस तरह का हमला सीधे तौर पर चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने तथा लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने का षड्यंत्र है। ये बातें अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष चौहान ने अभाविप के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही है । उन्होंने कहा कि, "देश को अस्थिर करने वाली ताकतों का वास्तविक चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। माओवादी विचारधारा लगातार देश को खोखला करने पर तुली हुई है तथा निर्दोष लोगों की हत्या करवा रही है। गढ़चिरोली का हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार तथा चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश है। अभाविप सरकार से इस घटना के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करती है।" ■

# श्रीलंका की घटना क्या भारत के लिए चेतावनी है ?

**21 अप्रैल को श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए 8 सिलसिलेवार आतंकी बम धमाकों में 253 लोगों की मौत हुई जबकि 500 सौ से ज्यादा लोग घायल हुए है। आतंकियों ने कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च और पश्चिम तटीय शहर नेगोंबे के सेंट सेबेस्टियन चर्च को अपना पहला निशाना बनाया। इसके बाद कोलंबो के तीन होटलों और बट्टीकलोआ के एक चर्च में धमाका हुआ। दोपहर बाद दो बम धमाके कोलंबो के चिड़ियाघर के पास हुए। श्रीलंका की इस आतंकी घटना ने एक बार फिर पूरे विश्व को झकझोर दिया है । घटना को श्रीलंका के मसाला कारोबारी के दो बेटों समेत नौ कुख्यात आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला आतंकी भी शामिल थी। बम धमाकों के करीब 56 घंटे बाद इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी। आईएस ने सिलसिलेवार बम धमाकों का वीडियो जारी किया था। इस आतंकी हमले से दशकों से आतंकी गतिविधियों से त्रस्त दक्षिण एशिया में शांति की पहल की उम्मीद को भी बड़ा झटका लगा है। ऐसे समय में जब भारत खुद पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां का दंश झेल रहा है तब पड़ोसी देश श्रीलंका में आइएस और नेशनल तौहीद जमात की उपस्थिति क्या भारत के लिए चेतावनी है इस विषय को केन्द्र में रखकर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के संवाददाता ने देशभर के लोगों से बात की और उसके विचार जाने । प्रस्तुत है कुछ चुनी हुई प्रतिक्रियाएं –**

श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों में करीब 300 से अधिक लोगों के मारे जाने से भारत सरकार के गुस्से व चिंता की वजह बेहद साफ है । श्रीलंका 80 के दशक से लेकर 2009 तक अलगाववादी संगठनों के आतंक से ग्रसित रहा और इसका बहुत ज्यादा असर भारत सरकार पर पड़ा है। इस हिंसा की वजह से सैकड़ों भारतीय सैनिकों की और प्रवासी भारतीयों की जाने गई। एक समय भारत के चार अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में लंबे समय तक अस्थिरता का वातावरण रहा है । इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा रहा है । पिछले कुछ समय नेपाल ,बांग्लादेश और श्रीलंका में शांति व स्थिरता के वातावरण बनने से एक नया रणनीतिक नजरिया बना था। पड़ोसी देश मे आतंक की दस्तक से भारत की चिंता की एक अन्य वजह यह भी है इस बार आतंक का चेहरा दूसरा है । श्रीलंका में हुए इस बड़े हमले के पीछे इस्लामिक चरमपंथी संगठन तौहीद-जमात का नाम सामने आ रहा है । चूंकि तौहीद जमात का लिंक भारत के तमिलनाडु से रहा है इसलिए भारत के लिए यह स्थिति और अधिक चिंताजनक हो जाती है। तमिलनाडु में यह संगठन सामाजिक कार्यो के माध्यम से खुद को जोड़ते हुए सक्रिय रहता है। ऐसे में यह आतंकी हमला भारत को फैसले लेने में मुश्किले बढ़ा सकता है।

- **राजीव रंजन**, जमशेदपुर

श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाके से न सिर्फ श्रीलंका को ही सतर्क होने की जरूरत है बल्कि पूरे विश्व को सतर्क होना होगा । आये दिन कोई न कोई देश आतंकियों के प्रकोप से पीड़ित होता जा रहा है । कुछ कहा नहीं जा सकता कब किस देश पर हमला हो जाए । जब बात भारत की आती है, तो कुछ देश ऐसे है,जो दोस्ती का नकाब पहन कर पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले हैं, श्रीलंका में हुए इस धमाके से हम देख सकते है अधिक सख्या में इस धमाके से शिकार होने वाले व्यक्ति भारतीय थे। यह भारत के लिए बड़ी ही दुःख और चिंता का विषय है । भारतीय नागरिक कहीं पर भी सुरक्षित नही है। भारत सरकार और भारतीय नागरिक को सतर्क होना होगा। आए दिन कोई न कोई देश आतंकियों से पीड़ित होता जा रहा है। जिससे जन धन की हानि हो रही है व आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं जिससे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्या देश में उत्पन्न हो रही है। विश्व संगठन समिति को आतंकियों के खिलाफ ठोस फैसले लेने होंगे तभी सुख शांति पूरे विश्व में अमल हो पायेगी।

- **बोबी गिलहरे,** (छात्रा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ )

एक तरफ जहाँ पूरा विश्व मानव कल्याण, विश्व कल्याण व सर्व धर्म सद्भाव की संकल्पना को सत्य करने हेतु प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर कट्टर मानसिकता से ओतप्रोत भय व हिंसा का माहौल बनाकर विश्वकुख्यात ISIS जैसे आतंकी संगठन मानव व मानवता की लगातार निर्मम हत्या कर रहे हैं। विभिन्न रक्षा विशेषज्ञों ने श्रीलंका में हुए आतंकी हमले का मुख्य कारण ख़ुफ़िया तंत्रो में भारी चूक को माना है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों की पड़ोस में उपस्थिति निश्चित रूप से भारत सहित सभी SAARC देशों के लिए ख़तरे की घंटी है जिससे सभी को साथ मिलकर बहुत मज़बूती के साथ निपटना होगा तभी आतंक रूपी दानवों का वध सम्भव हो पायेगा।आतंकवाद को किसी एक सीमा में बांधकर नही रखा जा सकता । जो भी देश इसके पोषक हैं या बनने की कोशिश करेंगे उन्हें भी यह भस्मासुर की भांति एक दिन भस्म कर देगा,पाकिस्तान के स्कूल व इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले से ये समझा जा सकता है। अटल जी ने सत्य कहा था..

"चिंगारी का खेल बुरा होता है,
औरों के घर आग लगाने का जो सपना,
अपने ही घर खरा होता है"...

इस आतंक रूपी चिंगारी से जितना दूर रहा जाय उतना ही मानव,धर्म तथा सम्पूर्ण विश्व हेतु उचित होगा।

- **अरुण श्रीवास्तव**( वाराणसी )

श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर आत्मघाती आतंकी हमला ना केवल श्रीलंका जैसे देश के लिए सबक है बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक सबक और चिंता का विषय है । यदि इस हमले को भारत के साथ जोड़कर देखा जाए तो श्रीलंका के सेना प्रमुख महेश सेनानायके ने दावा किया है कि श्रीलंका के आत्मघाती हमले के पीछे जितने भी आतंकवादी संलग्न है उनकी ट्रेनिंग भारत के कश्मीर और केरल में हुई हैं हालांकि भारत ने इस दावे को गलत बताया है लेकिन फिर भी हमें इन हमलों के पीछे गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है । इस प्रकार के हमले जो विश्व के विभिन्न कोनों में इस्लामिक स्टेट के द्वारा कराये जा रहे हैं जिसमें भारत कोई अछूता देश नहीं है। भारत जैसे देश में आतंकी संगठन सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। यह दिन-ब-दिन भारत के अन्य कोनो में भी फैलते जा रहे हैं जिसमें इन हमलों के पीछे का पूरा मकसद देश में अमन चैन की व्यवस्था को खोखला करना तथा देश के विकास को बाधा पहुंचाना और धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त करना है । जिस प्रकार से भारत में ही हाल ही के दिनों में जो आतंकवादी हमले हुए हैं चाहे वह पुलवामा का हमला हो या फिर मुंबई का 26 -11 का हमला जिसे आज भी लोग भुला नहीं सके हैं । इसलिए इस प्रकार के आतंकवादी हमले चाहे वह न्यूजीलैंड , पेशावर या फिर श्रीलंका का ही हो इन सबों को दिमाग में रखते हुए भारत को एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जिससे भारत अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर सके।

- **शुभम कुमार राय** (छात्र, सिदो - कान्हू मुर्मु विश्वविद्यालय, दुमका )

# आंदोलन

12 वीं परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियों के कारण लगातार हो रहे छात्रों की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर तेलगांना के राज्यपाल से मिला अभाविप शिष्टमंडल

भागलपुर (बिहार) : एसिड अटैक पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभाविप कार्यकर्ता

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 May 2019
Date of Publishing: 8 May, 2019

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi